जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

जालोर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोन:- 226422, 226423 फैक्स:- 02973-226424 वर्ष: 20 संख्या: 318 प्रभात जालोर, मंगलवार 24 फरवरी, 2026 पो. रजि. /RJ/SRO/9640/2022-24 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

लोकसभा अध्यक्ष अपने "डिस्क्रेशनरी फण्ड" का बहुत "सही" उपयोग कर रहे हैं!

अविश्वास प्रस्ताव को बेअसर करने के लिए, 60 देशों में सांसदों के प्रतिनिधिमंडल भेजे जाएंगे लोकसभा सचिवालय की ओर से, भारत की संसदीय व्यवस्था की सुंदर कहानी पेश करने के लिए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। क्या लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला अपने व्यक्तिगत पीआर के लिए राष्ट्रीय खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं?

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च को सदन में चर्चा के लिए लाया जाएगा। जब सदन एक ब्रेक के बाद फिर से चलेगा, उसी दिन प्रस्ताव लाया जाएगा।

सांसदों और अधिकारियों के बीच गुपचुप चर्चा हो रही है कि स्पीकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी तादाद में नेताओं व सांसदों को 60 देशों में भेजने का कार्यक्रम बनाया है।

विभिन्न समूह बनाए गए हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद के दौर में किए गए प्रयासों की तरह ही विभिन्न देशों के साथ संपर्क बनाने का

- इस मकसद से 60 से अधिक देशों के साथ संसदीय मित्रता ग्रुप बनाए गए हैं।
- विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं, जैसे पी. चिदम्बरम, शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद, टी.आर. बालू, के.सी. वेणुगोपाल, अखिलेश, ओवैसी, अभिषेक बनर्जी, सुप्रिया सूले, अनुराग ठाकुर आदि को संसदीय मित्रता ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया है।
- श्री लंका, जर्मनी, न्यूज़ीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, इज़रायल, अमेरिका, रूस, यूरोपीयन यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ईरान व यू.ए.ई., को भेजे जाने वाले ग्रुप्स गठित हो चुके हैं तथा साथ ही इस सूची में सम्मिलित नाम साठ की संख्या पार कर जाएंगे।
- ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्र.मंत्री ने भी कई ग्रुप्स बनाये थे, जिन्हें विदेश भेजा गया था तथा इन ग्रुप्स की यात्रा का काफी व्यापक व सकारात्मक असर हुआ था। ओम बिड़ला चाह रहे हैं कि संसदीय ग्रुप की वर्तमान विदेश यात्राओं से भी ऐसा ही नतीजा निकलेगा।
- यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोकसभाध्यक्ष के "डिस्क्रेशनरी फण्ड" का कोई ऑडिट नहीं होता, राष्ट्रपति के "डिस्क्रेशनरी फण्ड" की भांति। अतः संसदीय मंत्री ग्रुप्स की विदेश यात्राएं निर्विघ्न रूप से पूर्ण होगी शीघ्र ही।

कार्य करेंगे, ताकि भारत के दृष्टिकोण को सामने लाया जा सके।

कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ चल रही आलोचनाओं को दबाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रांची से दिल्ली जा रही एयर एंबुलैंस क्रैश

रांची, 23 फरवरी। रांची से एक मरीज को इलाज के लिए दिल्ली लेकर जा रही एक एयर एंबुलेंस सोमवार रात चतरा में क्रैश हो गई। इस विमान पर मरीज समेत कुल सात लोग सवार थे, जिनमें सभी की मौत हो गई।

बताया जाता है कि आग से गंभीर रूप से झुलसे, लातेहार के चंदवा निवासी मरीज संजय कुमार को शाम 7:11 बजे रांची के देवकमल अस्पताल से दिल्ली ले जाया जा रहा था।

रेड बर्ड एयरवेज़ प्राइवेट लिमिटेड के, बीच क्राफ्ट सी 90 एयर एंबुलेंस में

- चतरा जिले के पास सिमरिया में हुए हादसे में विमान में सवार मरीज सहित सभी सात लोगों की मौत हो गई।

मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी अर्चना देवी व एक अन्य स्वजन ध्रुव कुमार के अलावा एंबुलेस टीम के कैप्टन विवेक विकास भगत, कैप्टन स्वराज दीप सिंह, डॉ. विकास कुमार गुप्ता और पैरा मेडिकल स्टाफ सचिन कुमार गुप्ता सवार थे।

रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के निदेशक विनोद कुमार ने बताया कि शाम 7.34 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) से विमान का संपर्क अचानक टूट गया। संपर्क टूटते ही तत्काल हाई अलर्ट जारी कर दिया गया।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हरदीप पुरी के बारे में नया विवाद खड़ा हुआ, एप्स्टीन से संबंधों के बारे में

सोशल एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला ने पुरी का एप्स्टीन को लिखा एक पत्र ट्विटर पर डाला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। तथाकथित एपस्टीन फाइल्स से जुड़े नए खुलासों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन दावों में केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम फिर से जांच के दायरे में आने की बात कही जा रही है।

सोशल मीडिया और राजनीतिक मंचों पर फैल रहे ताजा दावों के अनुसार, पुरी ने वर्ष 2013 में एक ऐसे व्यक्ति को निजी पत्र लिखा था, जो बदनाम वित्त कारोबारी जैफरी एप्स्टीन का करीबी बताया जाता है। पत्र में कथित रूप से एक एहसान के लिए उन्होंने अपनी बेटी की ओर से धन्यवाद दिया गया था।

हाल ही में ऑनलाइन सामने आए दस्तावेजों के अनुसार, यह पत्र वर्ष 2013 का है, जब पुरी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।

यह पत्र, जो अब सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है, ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। विपक्षी दल और सिविल सोसायटी के

- इस पत्र के अनुसार, पुरी ने एप्स्टीन के एक नज़दीकी मित्र को 2013 में पत्र लिखकर धन्यवाद दिया, पुरी की पुत्री हिमानी पुरी की व्यवसायिक कंपनी में 2,400 करोड़ रूपए इन्वेस्ट करने के लिए। यह उस समय की बात है जब 2013 में, हरदीप पुरी भारत की "फॉरेन सर्विस" की पोस्ट, यू.एन. में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद से रिटायर हुए ही थे तथा उन पर आरोप था कि वे कंपनी से सम्बद्ध बिज़नेस के लिए "लॉबिंग" कर रहे थे।
- इस प्रसंग का एक रोचक पहलू यह भी है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा की बड़ी सुस्त सी प्रतिक्रिया आई। खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस इस प्रकरण से जुड़े कागज़ातों की सच्चाई व विश्वसनीयता का गहराई से अध्ययन कर रही है तथा निष्कर्ष पर पहुँचकर ही अपनी प्रतिक्रिया देगी।

कुछ वर्ग इस मामले में स्पष्टता की मांग कर रहे हैं।

विवाद ने तब जोर पकड़ा जब सामाजिक कार्यकर्ता कुणाल शुक्ला ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इसे पुरी का निजी पत्र बताया। अपनी पोस्ट में शुक्ला ने आरोप लगाया कि राजनयिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद पुरी न्यूयॉर्क में अपनी बेटी के कारोबारी हितों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, इस दस्तावेज की प्रामाणिकता और पत्राचार के संदर्भ की अब तक आधिकारिक स्रोतों से स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जल्दी ही अलवर तक भी आएगी रैपिड रेल

दिल्ली से मेरठ तक का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरु

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। भारत का पहला रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम (आरआरटीएस), जो दिल्ली से 82 किमी की दूर स्थित मेरठ को जोड़ेगा, अब पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को इस लाइन के अधूरे 26 किमी खंड का उद्घाटन किया। ट्रेनों का परिचालन 10 मिनट के अंतराल पर होगा, जो दिल्ली के सराय काले खान से लेकर मेरठ के मोदीपुरम तक की यात्रा 55 मिनट में पूरी करेंगी।

साथ ही, मेरठ मेट्रो का 23 किमी का खंड भी लॉन्च किया गया है- जो आरआरटीएस ट्रैकों और सिग्नलिंग सिस्टम का उपयोग करेगा। अधिकारियों ने कहा, इसे भारत की सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली के रूप में पेश किया गया है, जिसकी अधिकतम संचालन गति 120 किमी/घंटा होगी,

- प्रधानमंत्री ने रविवार को पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विधिवत् उद्घाटन किया।
- इसी बीच केन्द्रीय शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली-अलवर और दिल्ली-करनाल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कैबिनेट से मंजूरी मिलने की बात कही।
- पहले रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के शुभारंभ के साथ ही मेरठ मैट्रो का 23 किलोमीटर लंबा रेल खंड भी शुरु किया गया। अब देश का मैट्रो रेल नैटवर्क 1100 किलोमीटर तक बढ़ चुका है।

और पूरी यात्रा 30 मिनट में पूरी होगी। यात्री चार स्टेशनों पर आरआरटीएस और मेट्रो इंटरचेंज कर सकते हैं: मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगम पुल और मोदीपुरम।

अधिकारियों ने कहा, अब मेरठ के जुड़ने से, देश का मेट्रो नेटवर्क 24 शहरों में 1,100 किमी तक बढ़ चुका है।

180 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड और 160 किमी/घंटा की संचालन स्पीड के साथ, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस भारत का पहला परिवहन प्रोजेक्ट है, जो क्लस्टर-आधारित शहरी विकास की अवधारणा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन पुनः बिखराव की ओर

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। आगामी राज्य सभा और महाराष्ट्र विधान परिषद

- इस बार मसला है, राज्यसभा की रिक्त हुई सीटों का। महाराष्ट्र से राज्यसभा की सात सीटें खाली होंगी, इनमें से सिर्फ एक विपक्ष को मिलेगी और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तीनों घटक, शिव सेना, कांग्रेस व एनसीपी की इस एक सीट पर नज़र है।

चुनावों ने विपक्षी खेमें में हलचल मचा दी है और महा विकास अघाड़ी

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम में कांग्रेस से पलायन रोकना बड़ी चुनौती है प्रियंका के लिए

वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भूपेन बोरा ने भाजपा में शामिल होकर प्रियंका के लिए चुनौती बढ़ा दी है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए, कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने राज्य का दो दिवसीय दौरा पूरा किया। यह दौरा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी से इस्तीफा देने के कुछ ही दिन बाद हुआ।

करीब 30 वर्षों तक कांग्रेस में रहे बोरा, जो जुलाई 2021 से मई 2025 तक असम इकाई के अध्यक्ष रहे, ने शुक्रवार को पार्टी छोड़ दी। सूत्रों के अनुसार, जब से गौरव गोगोई उनकी जगह राज्य पार्टी अध्यक्ष बने हैं, तब से वे असहज महसूस कर रहे थे। उन्हें लगता था कि नए प्रदेश अध्यक्ष धुबरी के सांसद रकीबुल हुसैन को अधिक महत्व दे रहे हैं।

- प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष हैं और उन पर सही प्रत्याशियों के चयन की भी जिम्मेवारी है, साथ ही गठबंधन के लिए सही सहयोगियों की तलाश भी उन्हें करनी है। इसके लिए वे फूंक-फूंक कर कदम उठा रही हैं।
- अपने हालिया असम दौरे में उन्होंने राज्य के सभी कांग्रेसी विधायकों, सांसदों व जिला तथा ब्लॉक अध्यक्षों से भी मुलाकात की।
- सूत्रों का कहना है कि राज्य में भाजपा का संगठन काफी मजबूत है, कांग्रेस भले ही बड़ी जीत प्राप्त न कर पाए, पर, अगर उसने स्थिति पहले से बेहतर कर ली तो भी इससे प्रियंका की सफलता माना जाएगा।

शुक्रवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद, एनडीटीवी से बातचीत में बोरा ने कहा कि वे रविवार को भाजपा में शामिल होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि 8 मार्च तक कांग्रेस के कई अन्य नेता भी भाजपा में जा सकते हैं।

प्रियंका गांधी के लिए अब सबसे बड़ी प्राथमिकता इस संभावित पलायन को रोकना और चुनाव से पहले पार्टी को एकजुट रखना होगा।

स्क्रीनिंग कमेटी के अन्य सदस्यों में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री, डी के शिवकुमार छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सांसद इमरान मसूरद शामिल हैं। अपने दौरे के दौरान, गांधी ने असम के 21 विधायकों, तीन सांसदों, जिला अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों से मुलाकात की।

उम्मीदवारों के चयन के अलावा, गांधी और कांग्रेस के सामने एक और बड़ी चुनौती भाजपा का सामना करने के लिए सही सहयोगियों का चयन करना होगा। ज्ञातव्य है कि भाजपा लगातार दो कार्यकाल से सत्ता में है और चुनाव से पहले उसे बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। 2021 में, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने राज्य की 126 में से 75 सीटें जीती थीं, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत को केवल 50 सीटें मिली थीं।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

असम के सीमावर्ती गांवों पर भाजपा का फोकस

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। चुनाव आयोग द्वारा आगामी असम विधानसभा चुनावों की घोषणा चन्द सप्ताहों में किये जाने की उम्मीद के साथ, भारतीय

- गृह मंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती गांवों के लिए 6839 करोड़ रूपए की लागत से "वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम" शुरु किया।

जनता पार्टी ने अपनी चुनावी मुहिम तेज कर दी है।

भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन के असम दौरे के बाद, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दो दिवसीय असम यात्रा, 2026 के चुनावों के लिए भाजपा के प्रयासों को और गति देने का संकेत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ट्रंप कहा करते थे "टैरिफ" बहुत सुन्दर शब्द है

पर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी संपूर्ण गर्वोक्ति की हवा निकाल दी

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 फरवरी। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए टैरिफ (शुल्क) को रद्द करने से राष्ट्रपति को कई तरह से झटका लगा है। इससे उनके सर्वशक्तिमान होने के दावे को नुकसान पहुँचा है। इस फैसले ने उनके "टैरिफ" के प्रति लगाव को भी झटका दिया है। याद रहे, उन्होंने "टैरिफ" शब्द को सबसे सुंदर शब्द बताया था।

भारत के लिए यह ताज़ा फैसला कुछ अच्छी खबर लेकर आया है।

कम से कम शुरुआत में तो यह अंतरिम समझौता, जिसके तहत अमेरिकी सामान भारत में बिना टैक्स के आएगा और भारतीय सामान पर अमेरिका में 18 प्रतिशत शुल्क लगेगा, अब खत्म हो गया है। अब अमेरिकी सामान भारत में ड्यूटी फ्री नहीं आएगा और ट्रंप के फैसले के बाद सभी के लिए लगाए गए 10 प्रतिशत के वैश्विक टैरिफ के तहत 10 प्रतिशत शुल्क लगेगा।

अगले पाँच वर्षों में 500 अरब डॉलर की खरीद का जो वादा भारत ने किया था, जो कथित तौर पर इस अंतरिम व्यापार समझौते का हिस्सा माना जा रहा था, वह भी अब समाप्त हो गया है। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था। इसका मतलब था कि भारत को इस समझौते के तहत हर साल लगभग 100 अरब डॉलर का सामान अमेरिका से खरीदना होता।

महंगे रक्षा उपकरण, विमान और अन्य उच्च हाई टैक्नॉलजी वस्तुओं की खरीद पर बहुत बड़ी राशि खर्च हो सकती है। इनमें से अधिकतर पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू होता है और इन्हें खरीदने की भारत की पिछली कोशिशें कामयाब नहीं हुईं।

नई परिस्थितियों में जब व्यापार वार्ताकार एक नई व्यापार संधि पर चर्चा करेंगे, तो दोनों पक्षों के पास समझौते के लिए काफी गुंजाइश होगी। हालांकि,

- अतः ट्रंप अब जिद्दी, बिगड़ैल बच्चे की भांति कुछ और प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं, मित्र देशों को प्रोत्साहित व अमित्र देशों को प्रताड़ित करने के लिए।
- पर, इस अधरझूल स्थिति में, भारत के लिए खास बुरी खबर नहीं है। अब अमेरिकी सामान का ज़ीरो टैरिफ पर प्रवेश पाना व भारतीय सामान पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाने के लिए हुए समझौते भी अब लटक गए हैं। भारत का सामान अमेरिका में 10 प्रतिशत टैरिफ पर ही प्रवेश पा सकेगा तथा अमेरिकी सामान भी पुरानी कस्टम ड्यूटी की अदायगी के बाद भी भारत में भेजा जा सकेगा।

भविष्य के उस व्यापार समझौते की रूपरेखा पहले राजनीतिक नेतृत्व द्वारा तय की जाएगी। जब तक वार्ताकार विस्तार से काम शुरू करेंगे, तब तक चार साल कब बीत जाएँगे, पता नहीं चलेगा।

भारत को यू.एस. टैरिफ के ओवर ऑल रुख पर फैसले के असर का मूल्यांकन करने और डॉनल्ड ट्रंप आगे क्या कदम उठा सकते हैं, यह देखने का समय मिलेगा। वैसे भी, फैसले के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वादा किया है कि बाकी दुनिया को अमेरिका की ओर से कठोर टैरिफ और कदमों का सामना करना पड़ेगा।

प्रशासन जो भी कदम सोच सकता है, ट्रंप उसपर भड़क रहे हैं और कड़े उपाय तलाश रहे हैं। वे अन्य देशों के लिए बहुत नुकसानदायक कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अंत में इससे सबसे अधिक नुकसान उनके अपने नागरिकों को ही होगा, क्योंकि टैरिफ बढ़ेगा और व्यापार में बाधाएँ आने से अमेरिकियों पर ही सबसे ज्यादा असर पड़ेगा।

विशेषज्ञों को आशंका है कि आहत डॉनल्ड ट्रंप यू.एस. की इकॉनमी को ही ऐसे तरीकों से नुकसान पहुँचाना शुरु कर देंगे, जिससे गहरी मंदी आ सकती है। पिछली बार 1920 के दशक के अंत में जब बेहद विवादित स्मूट-हॉले अधिनियम पारित किया गया था, तो उसके बाद 1930 के दशक की महामंदी (ग्रेट डिप्रेशन) आई थी।

इसका असर केवल अमेरिकी नागरिकों पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा। भारत को इन सभी घटनाओं पर नजर रखनी चाहिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को इन प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने ट्रंप की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचाया है। वे यह दिखाते थे कि वे जो चाहें कर सकते हैं। लेकिन इस फैसले ने उन्हें उनकी सीमाएँ दिखा दी हैं, अब उन्हें कानून बनाने वाली संस्था से परामर्श और मंजूरी लेनी होगी। अब वे टैरिफ के विकल्प तलाश रहे हैं और बेसब्री से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इन्हें अमेरिकी कांग्रेस से अलग होकर कैसे लगाया जा सकता है।

ट्रंप ने टैरिफ का इस्तेमाल सिर्फ एक ट्रेड हथियार के रूप में नहीं किया, उन्होंने इसे अपने निजी हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया, उन लोगों और नेताओं के खिलाफ, जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे। जो भी उनकी बात नहीं मानता था, उसे टैरिफ लगाकर दंडित किया जाता था। एक देश को इसलिए सज़ा दी जाती थी, क्योंकि ट्रंप उस देश के प्रमुख के साथ व्यक्तिगत रूप से सहज नहीं थे।

राजनीतिक रूप से, यह फैसला मध्यावधि चुनावों से पहले आना उनके

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अनिल अंबानी पर बैंक की कार्यवाही से रोक हटी

मुंबई, 23 फरवरी। उद्योगपति अनिल अंबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट से सोमवार झटका लगा। अदालत ने वह स्टे आदेश हटा दिया, जिसने बैंकों को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक रखा था। कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल जज की उस अंतरिम राहत को

- बॉम्बे हाईकोर्ट की डबल बैंच ने सिंगल बैंच का स्टे हटाया।

रद्द कर दिया, जिसमें तीन बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और आईडीबीआई बैंक तथा ऑडिटर बीडीओ इंडिया एलएलपी को कार्रवाई से रोका गया था।

यह पूरा मामला आरबीआई की 2024 मास्टर डायरेक्शंस ऑन फ्रॉड क्लासिफिकेशन से जुड़ा है। सिंगल जज ने दिसंबर 2025 में अनिल अंबानी को राहत देते हुए कहा था कि फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करने वाले

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)